

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश

1, तिनक मार्ग लखनऊ 226001

पत्र संख्या: डीजी-परिपत्र सं-02 /2015

दिनांक: जनवरी 10, 2015

- 1-समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, 30प्र0,
- 2-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, 30प्र0,
- 3-समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समस्त प्रभारी, जनपद उत्तर प्रदेश।

विषय:- मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे गम्भीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु विशेष अनुज्ञा याचिका(क्रि0) संख्या-5073/2011 स्टेट आफ कर्नाटका बाई नोनाविन्करे पुलिस वनाम शिवन्ना उर्फ तरकारी विशन्ना में दिनांक 25-04-2014 को पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे गम्भीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्यवाही एवं प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत दिनांक 25-04-2014 को आदेश पारित किया है। पारित आदेश के अनुपालन में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। आदेश के प्रस्तर-9 में दिये गये निर्देश निम्नलिखित हैं:-

'9- On considering the same, we have accepted the suggestion offered by the learned counsel who appeared before us and hence exercising powers under Article 142 of the Constitution, we are pleased to issue interim directions in the form of mandamus to all the police station in charge in the entire country to follow the direction of this Court which are as follows:

(i) Upon receipt of information relating to the commission of offence of rape, the Investigating Officer shall make immediate steps to take the victim to any Metropolitan/preferably Judicial Magistrate for the purpose of recording her statement under Section 164 Cr.P.C. A copy of the statement under Section 164 Cr.P.C. should be handed over to the Investigating Officer immediately with a specific direction that the contents of such statement under Section 164 Cr.P.C. should not be disclosed to any person till charge sheet/report under Section 173 Cr.P.C. is filed.

(ii) The Investigating Officer shall as far as possible take the victim to the nearest Lady Metropolitan/preferably Lady Judicial Magistrate.

(iii) The Investigating Officer shall record specifically the date and the time at which he learnt about the commission of the offence of rape and the date and time at which he took the victim to the Metropolitan/preferably Lady Judicial Magistrate as aforesaid.

(iv) If there is any delay exceeding 24 hours in taking the victim to the Magistrate, the Investigating Officer should record the reasons for the same in the case diary and hand over a copy of the same to the Magistrate.

(v) Medical Examination of the victim: Section 164 A Cr.P.C. inserted by Act 25 of 2005 in Cr.P.C. imposes an obligation on the part of Investigating Officer to get the victim of the rape immediately medically examined. A copy of the report of such medical examination should be immediately handed over to the Magistrate who records the statement of the victim under Section 164 Cr.P.C.

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि बलात्कार एवं सामूहिक बलात्कार जैसे गम्भीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्यवाही एवं प्रकरण के शीघ्र निस्तारण के दृष्टिगत मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों से अपने जनपदों के समस्त थानों के प्रभारी अधिकारी को अवगत कराते हुए अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराये।

प्रकरण अति महत्वपूर्ण है, इसमें किसी प्रकार की शिथिलता/लापरवाही न की जाए।

(अरूण कुमार गुप्ता)

पुलिस महानिदेशक,

उत्तर प्रदेश।